



वर्देशी वशिववदियालयों हेतु UGC द्वारा मसौदा मानदंड की घोषणा

प्रलिमिंस के लयि:

यूजीसी, NEP 2020

मेन्स के लयि:

वर्देशी वशिववदियालयों के लयि यूजीसी द्वारा मसौदा मानदंड की घोषणा और इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

वशिववदियालय अनुदान आयोग (UGC) ने मसौदा नयिम जारी कयि हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वशिववदियालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लयि भारत में कैंपस खोलना आसान बनाएंगे और उन्हें नरिणय लेने की स्वायत्तता प्रदान करेंगे।

FOREIGN universities in the top 500 category in world rankings can apply **WILL BE FREE** to fix their admission criteria and fee structure

AUTONOMY to recruit faculty and staff from India and abroad

CAN REPATRIATE funds to home jurisdiction

SHALL NOT offer any programme that jeopardises India's national interest

यूजीसी द्वारा घोषति मसौदा मानदंड:

- मापदंड नरिधारण:
 - भारत में परसिर स्थापति करने के लयि एक अंतर्राष्ट्रीय वशिववदियालय जसि वशिव भर के शीर्ष 500 वशिववदियालयों में स्थान दया गया है या एक वर्देशी शैक्षणिक संस्थान जो अपने देश में अच्छी स्थति में है, यूजीसी को आवेदन दे सकता है।
- आवेदन प्रकरयि:
 - यूजीसी द्वारा नयिक्त एक स्थायी समति इस आवेदन पर वचिर करेगी जो संस्थान की वशिवसनीयता, प्रस्तावति कारयक्रमों, उसकी कषमता का आकलन करने के बाद 45 दनिों के भीतर अपनी सफिरारशिं प्रसतुत करेगी।
 - यूजीसी इसके बाद 45 दनिों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वशिववदियालय को दो वर्ष के भीतर भारत में कैंपस खोलने की प्रारंभिक मंजूरी दे सकता है।
 - आरंभिक मंजूरी 10 वर्ष के लयि होगी, जसि बढ़ाया जा सकता है।
- शकिषण का तरीका:

- उन्हें भारत और वदेशसे फ़ैकल्टी एवं स्टाफ़ की भरती करने संबंधी स्वायत्तता होगी।
- पाठ्यक्रम ऑनलाइन तथा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड में नहीं चलाए जा सकेंगे।
- भारतीय परसिर में छात्रों को दी जाने वाली डिग्रियाँ उनके मूल देश में संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियों के समकक्ष होनी चाहिये।
- ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्ययन का ऐसा कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जो भारत के राष्ट्रीय हति या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता हो।

■ नधि प्रबंधन:

- वदेशी विश्वविद्यालयों को मूल परसिरों में धन प्रत्यावर्तित करने की अनुमति होगी।
- धन की सीमा पार आवाजाही और वदेशी मुद्रा खातों का रखरखाव, भुगतान का तरीका, प्रेषण, प्रत्यावर्तन आदि वदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 एवं इसके नधियों के अनुरूप होगी।
- इसके पास अपनी फ़ीस संरचना तय करने की स्वायत्तता भी होगी और भारतीय संस्थानों पर लगाए गए किसी भी सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुल्क "उचित एवं पारदर्शी होना चाहिये।

पहल का महत्त्व:

- वदेश मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में करीब 13 लाख छात्र वदेश में पढ़ रहे थे और RBI के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-2022 में छात्रों के वदेश जाने के कारण वदेशी मुद्रा में 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
- वदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने से यह भी सुनिश्चित होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे लगभग 40 मिलियन छात्रों की वैश्विक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच होगी।
- भारत में वदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस की स्थापना के आदर्श का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP) 2020 में भी किया गया है।
 - NEP के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को वधायी ढाँचे के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
 - ये मसौदा नधिम केवल NEP के दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने की कोशिश करते हैं।
- यह कदम भारत को शिक्षा के लिये वैश्विक गंतव्य बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह न केवल वदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के प्रतभा पलायन और वदेशी मुद्रा के नुकसान को रोकने में मदद करेगा बल्कि वदेशी छात्रों को भारत में आकर्षित करने में भी मदद करेगा।
- यह देश में वभिन्न अभिकेर्तताओं के बीच प्रतसिपर्द्धा को प्रोत्साहित करेगा और वभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच संकाय से संकाय अनुसंधान सहयोग की अनुमति देगा।
- अमेरिका, ब्रिटन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चीनी छात्रों के बाद भारतीय वदेशी छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- ऐसा माना जाता है कि सामाजिक न्याय के सरोकारों की उपेक्षा की गई है जो कि भारत के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिये बहुत प्रभावी साधन है।
- मसौदा नधियों में छात्र प्रवेश में जाति आधारित/आर्थिक आधारित/अल्पसंख्यक आधारित/सशस्त्र बल आधारित/द्वियांग आधारित/कश्मीरी प्रवासियों/प्रतनिधित्व आधारित/महिला आरक्षण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- शैक्षिक व्यवसायियों के एक वर्ग ने भारत में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को संचालित करने की अनुमति देने के बारे में आपत्त व्यक्त की है क्योंकि इससे शिक्षा की लागत बढ़ जाएगी, जिससे यह आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुँच से बाहर हो जाएगी।
- वदेश में स्थित मूल संस्थानों को धन का प्रत्यावर्तन, जो कि पहले प्रतबिधित था, को अब अनुमति दे दी गई है।
- भारत में कार्य करने के लिये वदेशी शिक्षा प्रदाताओं को कोष निर्माण हेतु किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है

आगे की राह

- यदि भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तो भारत विश्व गुरु न सही कतिफरि से भारतीय समाज ज्ञानवान बनने की राह में एक कदम आगे होगा।
- संरक्षणवाद हमारी बौद्धिक सीमाओं को बंद नहीं करता, अपत्ति प्रतसिपर्द्धा और सर्वश्रेष्ठ के साथ सहयोगवास्तव में भारतीय पुनर्जागरण की दशा में सहायक होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. संवधान के नमिनलखिति प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवी अनुसूची

4. छठी अनुसूची
5. सातवी अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न 1. भारत में डिजिटल पहल ने देश में शिक्षा प्रणाली के कामकाज में कैसे योगदान दिया है? अपने उत्तर की वस्तुतः व्याख्या कीजिये। (2020)

प्रश्न 2. जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का उल्लेख कीजिये। (2021)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-norms-announced-by-ugc-for-foreign-universities>

